

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

यदि हम पिछले महीने की घटनाओं पर विचार करें तो, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि जल संसाधन प्रबंधन और बांध सुरक्षा की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

15.08.2023 को देश ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने प्रतिष्ठित लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में स्थापित जल शक्ति मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय के समर्पण पर प्रकाश डाला। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया है, जो हर घर में शुद्ध पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, केंद्रीय जल आयोग(मुख्यालय), नई दिल्ली में एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज समारोहपूर्वक फहराया गया। उत्साहपूर्ण तिरंगा रैली के साथ जश्न जारी रहा। पूरे देश में फैले सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्साहपूर्वक 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। उत्सव में इस अवसर को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में संगठन की देशभक्ति की भावना और एकता को प्रदर्शित करती है।

के.ज.आ. के प्रमुख कार्यात्मक डोमेन में से एक बाढ़ पूर्वानुमान है। सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के हमारे चल रहे प्रयासों में, हमने "फ्लडवॉच" मोबाइल ऐप सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इन-हाउस विकसित ऐप 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करता है। इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस, पठनीय और ऑडियो प्रसारण, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्धता इसे जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। इस ऐप को विकसित करने में मिस लवी

अग्रवाल, एडी का योगदान सराहनीय है। यह जानकर खुशी हो रही है कि के.ज.आ. के अधिक से अधिक अधिकारी कार्यों में नवीनता लाने के प्रयास कर रहे हैं।

के.ज.आ. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और चरण III के कार्यान्वयन में सहायक है। इसमें उन्नीस राज्य और तीन केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के लिए अनुबंध समझौते पर 14.08.2023 को हस्ताक्षर किए गए, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस संबंध में पूरी टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए मैं उनकी हार्दिक सराहना करता हूं।

इसके अलावा, अगस्त 2023 में चार अतिरिक्त जलाशयों को शामिल करने के साथ, हमारे जलाशय निगरानी प्रयासों का विस्तार हुआ है। केंद्रीय जल आयोग अब साप्ताहिक आधार पर देश भर में 150 जलाशयों के वास्तविक समय के भंडारण स्तर की निगरानी करता है। सूखा शमन प्रयासों में जलाशय की भंडारण स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। के.ज.आ. इस संबंध में फसल मौसम निगरानी समूह को नियमित अपडेट प्रदान करता है।

हम बांध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। विभिन्न स्थानों पर बांध अधिकारियों और राज्य अधिकारियों के सहयोग से सांस्कृतिक और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिससे समुदाय की भावना को बढ़ावा मिला और हमारे जल बुनियादी ढांचे के महत्व की सराहना हुई।

मैं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और के.ज.आ. के प्रत्येक सदस्य को उनके अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर देश में जल संसाधन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।



विषयसूची

एनडीएसए और डीआरआईपी

- बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी, रूड़की के साथ चर्चा।
- बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तकनीकी समिति
- डीआरआईपी II और III का कार्यान्वयन और भारत में बांध सुरक्षा प्रतिमान पर चर्चा
- बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तकनीकी समिति
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और चरण III के तहत केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श (ईएमसी) सेवाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर

- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) से संबंधित विभिन्न मुद्दों
- अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, 2023 के आयोजन के लिए मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु संचालन समिति की तीसरी बैठक

परियोजना के संबंध में बैठक

- नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता का मुद्दा
- उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 31वीं बैठक
- रेणुकाजी बांध परियोजना
- लखवार परियोजना
- कनाडा में 7 से 18 अगस्त 2023 तक बांध सुरक्षा और प्रबंधन पर कनाडा-भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

- भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जल दरों और भौतिक और वित्तीय पहलुओं के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति पर कार्यशाला
- 7वीं लघु सिंचाई जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना और झरनों की पहली जनगणना पर पहली अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला

अन्य गतिविधियाँ

- परामर्शदात्री निगरानी समिति की चौथी बैठक
- 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस और 74वीं आईईसी बैठक के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक
- फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए समिति की बैठक
- 'बाढ़ निगरानी' मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ

एनडीएसए और डीआरआईपी

बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी, रूड़की के साथ चर्चा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 01.08.2023 को आईआईटी रूड़की के.ज.आ. में बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में आईआईटी रूड़की के निदेशक के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री विजय सरन, सीई, डीएसओ, श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री अनिल जैन, सीई डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारी उपस्थित थे; और आईआईटी रूड़की से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आईआईटी रूड़की के निदेशक श्री के.के.पंत ने किया।

चल रही डीआरआईपी चरण II और III योजना के तहत, आईआईटी रूड़की में बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) की स्थापना के लिए 14.02.2023 को आईआईटी-रूड़की और के.ज.आ., जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार, केंद्र जलाशय अवसादन प्रबंधन और भूकंपीय खतरा मानचित्रण और बांधों के विश्लेषण के व्यापक विषयों पर मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान करेगा। आई सी ईडी वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से बांध सुरक्षा में आने वाली विभिन्न उभरती चुनौतियों के लिए विशेष तकनीकी सहायता और समाधान प्रदान करने के लिए एमओजेएस की तकनीकी शाखा के



रूप में भी कार्य करेगा। यह नियमित आधार पर केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण/ज्ञान भी प्रदान करेगा। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने के.ज.आ. और आईआईटी रूड़की के बीच लंबे सहयोग पर प्रकाश डाला और आईसीईडी के लिए आईआईटी रूड़की के शामिल होने का स्वागत किया। उन्होंने देश में बांध मालिकों के सामने आने वाले व्यावहारिक मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बांध सुरक्षा क्षेत्र में केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और पीएसयू अधिकारियों की क्षमता निर्माण सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी जिसे आईसीईडी को इस सहयोग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तकनीकी समिति

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर) ने के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2023 को जयपुर में बांध सुरक्षा (आईसीडीएस) 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए हाइब्रिड मोड में तकनीकी समिति (टीसी) की दूसरी बैठक में भाग लिया। बैठक में के.ज.आ., डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एनडीएसए, विश्व बैंक, आईआईटी रूड़की और

आईआईएससी बेंगलुरु के अधिकारी भी शामिल हुए।

इस बैठक में तकनीकी कागजात और प्रस्तुतियों की जांच, तकनीकी सत्रों के लिए अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष को अंतिम रूप देने, मौखिक या भौतिक दस्तावेज़ के मानक टेम्पलेट को अंतिम रूप देने आदि से संबंधित मामले पर चर्चा की गई है।

डीआरआईपी II और III का कार्यान्वयन और भारत में बांध सुरक्षा प्रतिमान पर चर्चा

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर) ने 07.08.2023 को समिति कक्ष-सी, संसदीय उपभवन, नई दिल्ली में डीआरआईपी II और III के कार्यान्वयन और भारत में बांध सुरक्षा

प्रतिमान पर चर्चा हेतु सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के बाद भारत में बांध सुरक्षा प्रतिमान और डीआरआईपी II और III का कार्यान्वयन बैठक के एजेंडे थे।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और चरण III के तहत केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श (ईएमसी) सेवाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर

श्री संजय कुमार सिब्ल, सदस्य (डी एंड आर) ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और चरण III के तहत केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श (ईएमसी) सेवाओं के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में भाग लिया। श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ.के नेतृत्व में सीपीएमयू और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी ने संयुक्त उद्यम के साथ डीआरआईपी चरण II और III सहित जेवी एसएमईसी-स्टकी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए 10 साल की अवधि के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श के लिए 14 अगस्त 2023 को श्रीमती देवाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, श्री एस.के.सिब्ल, सदस्य डी एंड आर, के.ज.आ. और श्री आनंद मोहन, जेएस आरडी और पीपी, डीओडब्ल्यूआर की उपस्थिति में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध पर हस्ताक्षर के दौरान श्री एस.एस.बख्शी, निदेशक, डीएसआर और श्री सिद्धांत आज़ाद, उप.निदेशक, डीएसआर भी उपस्थित थे।

जल शक्ति मंत्रालय बाह्य वित्तपोषित योजना ड्रिप चरण II और चरण III को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में उन्नीस (19) राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना) के लिए प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल; केंद्रीय जल आयोग, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और दामोदर घाटी निगम)। बजट परिव्यय 736 बांधों के पुनर्वास के लिए 10,211 करोड़ रुपये (चरण II: 5107 करोड़ रुपये; चरण III: 5104 करोड़ रुपये) प्रावधान है।

इस योजना की अवधि 10 वर्ष है, जिसे दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक छह साल की अवधि के साथ दो साल का



ओवरलैपिंग होगा। प्रत्येक चरण में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाहरी सहायता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर, 2020 को इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के दूसरे चरण को दो बहु-पक्षीय निधिकरण एजेंसियों-विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बैंक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि दी गई है।

विश्व बैंक के साथ ऋण (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पर हस्ताक्षर अगस्त, 2021 में गए थे जिसमें 10 राज्यों (गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़) ने भाग लिया था। द्वितीय चरण को विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2021 में प्रभावी घोषित किया गया था। मई 2022 में एआईआईबी के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विश्व बैंक द्वारा जून 2022 में चार अतिरिक्त राज्यों (कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को शामिल करने हेतु अधिसूचित किया गया था और उनका ऋण जनवरी, 2023 में प्रभावी घोषित किया गया था।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) से संबंधित विभिन्न मुद्दे

श्री संजय कुमार सिब्ल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर) ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), चरण- II और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 18.08.2023 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में चर्चा के एजेंडा बिंदु इस प्रकार हैं:-

- देश में निर्दिष्ट बांधों के राष्ट्रीय स्तर के डेटा बेस के अद्यतनीकरण की प्रगति।
- डीआरआईपी (ईएमसी) के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया।
- बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना।
- बांधों के भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन केंद्र की स्थापना के लिए एमएनआईटी का प्रस्ताव।
- धर्मा पोर्टल का कार्यान्वयन।

- एनडब्ल्यूए पुणे, सीएसएमआरएस और एनआईटी राउरकेला के प्रस्तावों की स्थिति।
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 के अनुपालन में एनडीएसए द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्थिति।
- एनसीडीएस की उप-समितियों का गठन।
- एनडीएसए के लिए पदों का सृजन, आरआर का गठन और पदों को भरना।
- एनडीएसए के लिए कार्यालय स्थान।
- बांधों के निरीक्षण की स्थिति (मानसून पूर्व और मानसून के बाद)।
- आईआईटी, दिल्ली द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट।
- बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
- गैर-निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा।
- डीआरआईपी की तकनीकी समिति की दूसरी बैठक।

अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, 2023 के आयोजन के लिए मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु संचालन समिति की तीसरी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर) ने 23.08.2023 को शाम 4 बजे समिति कक्ष, एसएसबी में विशेष सचिव, डीओडब्ल्यूआर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा

सम्मेलन, 2023 के संगठन के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए संचालन समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया। बैठक में सम्मेलन की कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी।

परियोजना के संबंध में बैठक

नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता का मुद्दा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 01.08.2023 को 14:30 बजे नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे पर बैठक में भाग लिया। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस/वर्चुअल मोड के माध्यम से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बीबीएमबी राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा की

गई। इससे पहले नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे पर 17.05.2023 को बैठक हुई थी। माननीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 07.08.2023 को 16:00 बजे क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और के.ज.आ., बीबीएमबी और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

उत्तरी कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 31वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 31वीं बैठक 25 अगस्त 2023 को के.ज.आ., नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में डीओडब्ल्यूआर, के.ज.आ. मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और वैपकॉस के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा विषयों जैसे बिहार/झारखंड जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकॉस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, वैपकॉस द्वारा बिहार में आरडी 31.4 से 68.37 किमी तक आरएमसी और इसकी संरचनाओं की अस्तरण मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया के लिए मात्रा तय करना पर विचार करना, झारखंड सरकार और वैपकॉस के पास जमा शेष राशि के खर्च की स्थिति आदि पर चर्चा हुई। निविदा प्रक्रिया के लिए मात्रा पर विचार करने और उसे पुख्ता करने के एजेंडा बिंदु पर,



टीईसी ने निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित मात्रा और लागत में कोई बदलाव करने का सुझाव नहीं दिया। टीईसी ने जल संसाधन विभाग, झारखंड के सदस्य को शेष राशि वापस करने के लिए अपने विभाग के साथ मामला उठाने का सुझाव दिया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य के लिए इसे जारी किया गया था, उसके लिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

पुनात्सांगछू-1 जलविद्युत परियोजना पर अंतर सरकारी समूह (आईजीजी) द्वारा प्रस्तुति

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और सचिव, पावर कमेटी

रेणुकाजी बांध परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 18.08.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से के.ज.आ. की चौथी मंजिल पर अपने कक्ष में रेणुकाजी बांध स्थल पर क्षेत्रीय जांच कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ., सीएसएमआरएस, जीएसआई, एचपीपीसीएल और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के पैनल के अधिकारियों के बीच बुलाई गई थी।

रूम, प्रथम तल, सी-विंग, जल संसाधन विभाग, एसएसबी की उपस्थिति में 14.08.2023 प्रातः 10.30 बजे पुनात्सांगछू-1 जलविद्युत परियोजना पर अंतर सरकारी समूह (आईजीजी) की प्रस्तुति में भाग लिया।

लखवार परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 21.08.2023 को दोपहर 3 बजे सम्मेलन कक्ष तीसरी मंजिल, के.ज.आ. में लखवार बहुद्देशीय परियोजना कार्यों और संबंधित अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों, परियोजना प्राधिकरणों और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) के बीच ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की।

कनाडा में 7 से 18 अगस्त 2023 तक बांध सुरक्षा और प्रबंधन पर कनाडा-भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

प्रशिक्षण में एम ओजेएस/के.ज.आ. के 10 अधिकारियों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों से 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य एक मंच स्थापित करना था जो बांध सुरक्षा विशेषज्ञों, चिकित्सकों, सुविधा मालिकों, ऑपरेटरों, नीति निर्माताओं और प्रबंधकों के बीच सहयोग प्रदान करता है।

प्रशिक्षण में कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में कक्षा व्याख्यान और प्रयोगशालाओं एवं बांध स्थलों का दौरा शामिल था।



भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जल दरों और भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति पर कार्यशाला

आईएसओ, के.ज.आ. द्वारा "भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जल दरों और भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति" पर दिनांक 24.08.2023 को नई दिल्ली में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई थी-

कार्यशाला के अवसर पर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत सरकार, राज्य सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जल और सिंचाई पेशेवरों, वित्त विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पानी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए किसी देश के नागरिकों को विश्वसनीय जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसकी सिंचाई प्रणाली को देश की खाद्य

7वीं लघु सिंचाई जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना और झरनों की पहली जनगणना पर पहली अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला

लघु सिंचाई की 7वीं जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना और "सिंचाई जनगणना" योजना के तहत झरनों की पहली जनगणना के संचालन के लिए पहली अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला 17 अगस्त, 2023 को श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई। सबसे पहले, डीडीजी, एमआई (स्टेट) ने सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, अध्यक्ष, के.ज.आ., नीति आयोग और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों का इस आयोजन का हिस्सा बनने और अपनी उपस्थिति से इसकी शोभा बढ़ाने के लिए का स्वागत किया। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई जनगणना" के तहत अब तक आयोजित लघु सिंचाई जनगणना और पहली जल निकाय जनगणना का संक्षिप्त परिचय और पृष्ठभूमि दी। आगे बताया गया कि,



आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज का उत्पादन करना होगा और उद्योगों हेतु भी आवश्यक जल आपूर्ति का आश्वासन देना होगा।



सभी चार जनगणनाएं समय और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने के साथ पुरानी पद्धतियों को प्रतिस्थापित करते हुए पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएंगी। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने अपनी समापन टिप्पणी में राज्यों को योजनाबद्ध समयसीमा के भीतर कुशल परिणाम लाने के लिए जनगणना की समयसीमा का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने इन जनगणनाओं के संचालन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियाँ

परामर्शदात्री निगरानी समिति की चौथी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने डीएचआई द्वारा किए जा रहे "रतले जलविद्युत परियोजना (जे एंड के) के जलाशय अवसादन के लिए 2 डी और 3 डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन" की निगरानी के लिए 08.08.2023 को अपराह्न 4 बजे के.ज.आ. के चौथे तल पर परामर्शदात्री निगरानी समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन्स (एन एंड डब्ल्यू), श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू), के.ज.आ. और एनएचपीसी के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए।



तलछट विश्लेषण-तटस्थ विशेषज्ञ (एनई) से संबंधित मामलों के लिए अभ्यावेदन को अंतिम रूप देना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने तलछट विश्लेषण-तटस्थ विशेषज्ञ (एनई) से संबंधित मामलों के लिए स्मारक को अंतिम रूप देने के संबंध में के.ज.आ. के अध्यक्ष, श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठकों में भाग लिया। पूर्वोत्तर कार्यवाही-सिंधु जल संधि

के लिए "ड्राफ्ट अभ्यावेदन अध्याय-6" को अंतिम रूप देने के लिए "तकनीकी उप-समिति" की 9वीं बैठक 17.08.2023 को शाम 5 बजे आयोजित की गई और 'तकनीकी उप-समिति' की 10वीं बैठक 19.08.2023 को के.ज.आ. में आयोजित की गई।

तटस्थ विशेषज्ञ की दूसरी बैठक

भारत और पाकिस्तान के बीच आईडब्ल्यूटी मुद्दों पर मतभेदों को सुलझाने के लिए नियुक्त एनई की दूसरी बैठक 20-21 सितंबर के दौरान वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई थी, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री एस.के. सिब्बल (सदस्य, डी एंड आर), श्री नरेंद्र सिंह शेखावत (निदेशक) और एम.एस. हर्षिता (उप निदेशक) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिन्होंने बैठक में भाग लिया। भारतीय

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने किया।

विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IX के तहत विशेष रूप से किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में दोनों देशों के बीच तकनीकी मतभेद को संबोधित करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था।

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस और 74वीं आईसीआईडी बैठक के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक

25वीं आईसीआईडी कांग्रेस और 74वीं आईसीआईडी बैठक के आयोजन की योजना बनाने और सलाह देने के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक 25.08.2023 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

आईएनसीआईडी ने आईएनसीआईडी, आईसीआईडी और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है और वैपकॉस को कार्यक्रम के आयोजन प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार इस आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पंजीकरण तथा प्रायोजन से राजस्व लगभग 2.20 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान, भारत सरकार द्वारा शेष 3.05 करोड़ रुपये की राशि (आयोजन के लिए अनुमानित कुल व्यय 10.25 करोड़ रुपये में से) को कवर करने का प्रस्ताव रखा गया और वित्त मंत्रालय से अनुमोदन मांगा जा सकता है।

"परियोजनाओं की स्थिरता के लिए तलछट प्रबंधन का महत्व" शीर्षक वाले ड्राफ्ट अभ्यावेदन अध्याय 6 पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी उप-समिति की 8वीं बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने "परियोजनाओं की स्थिरता के लिए तलछट प्रबंधन का महत्व" शीर्षक वाले ड्राफ्ट मेमोरियल अध्याय 6 पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए के.ज.आ. के

अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में 09.08.2023 को के.ज.आ. में तकनीकी उप-समिति की 8वीं बैठक में भाग लिया।

फरक्का में गंगा/गंगा जल बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए समिति की बैठक

"फरक्का में गंगा/गंगा जल के बंटवारे पर 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि की आंतरिक समीक्षा" करने के लिए समिति के संबंध में श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 22.08.2023 को सुबह 11 बजे

सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, के.ज.आ. में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समिति के विभिन्न टीओआर पर चर्चा की गयी।

'फ्लड वॉच' मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ

के.ज.आ. के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने मीडिया और बाढ़ आपदा निगरानी अधिकारियों की उपस्थिति में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप 'फ्लड वॉच' लॉन्च किया।

"फ्लडवॉच" सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। इस ऐप की मदद से उपयोगकर्ता देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस किसी के लिए भी जानकारी प्राप्त करना और बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करना आसान बना देगा।

इन-हाउस विकसित उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप में पठनीय और ऑडियो प्रसारण है और सभी जानकारी 2 भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। ऐप की मुख्य विशेषता में वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी शामिल है जहां उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की नवीनतम स्थितियों की जांच कर सकते हैं। ऐप विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के

देश में बाढ़ की स्थिति -अगस्त 2023

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 अगस्त 2023 की अवधि के दौरान, कुल 4876 (3791 स्तर + 1085 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 4625 (3612 स्तर+1013प्रवाह) पूर्वानुमान 94.85% प्रतिशत सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 31 अगस्त तक 71 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 124 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए थे।

01.05.2023 से 31.08.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

04 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	एनसीटी दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	यमुना	दिल्लीरेलवे ब्रिज	12/07/2023 13	15/07/2023 09
2	उत्तर प्रदेश	बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	14/07/2023 22 16/07/2023 11 29/07/2023 18	15/07/2023 18 22/07/2023 04 31/08/2023 23
3	असम	शिवसागर	दिखोव	शिवसागर	17/07/2023 05	17/07/2023 13
4	तेलंगाना	कुमुराम भीम	वर्धा	सिरपुर नगर	24/07/2023 13 29/07/2023 05	24/07/2023 18 29/07/2023 21

38 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 69 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर



नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है। ऐप निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ संबंधी सलाह देख सकते हैं। ऐप को एंड्रॉइड फोन के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। इसे जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

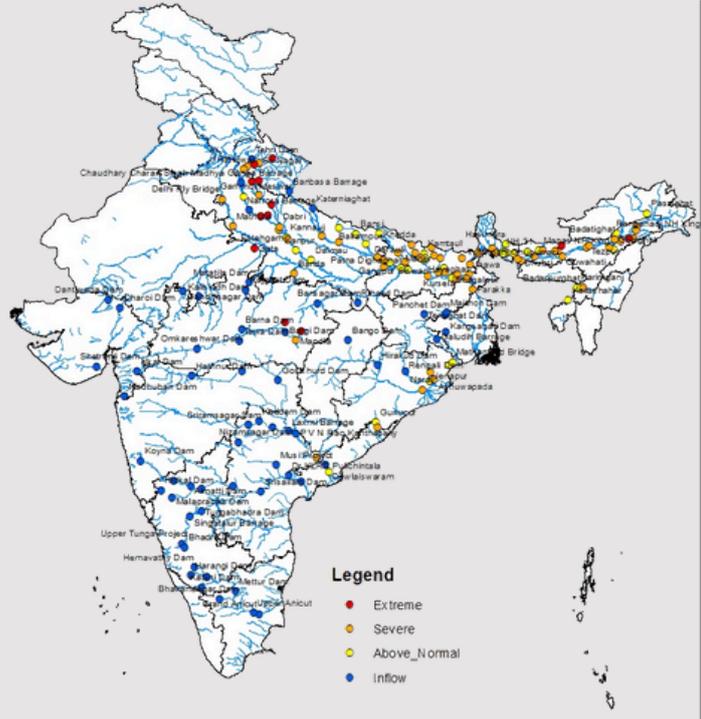
हवेली, ओडिशा और झारखंड में 51 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और ओडिशा में 42 एफएफ स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा-रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 61 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ।



31.08.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्ट: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2023-24)	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	43.9259	27.09%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	3.827	1.91%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	3.321	16.35%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	1.5376	13.98%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58		

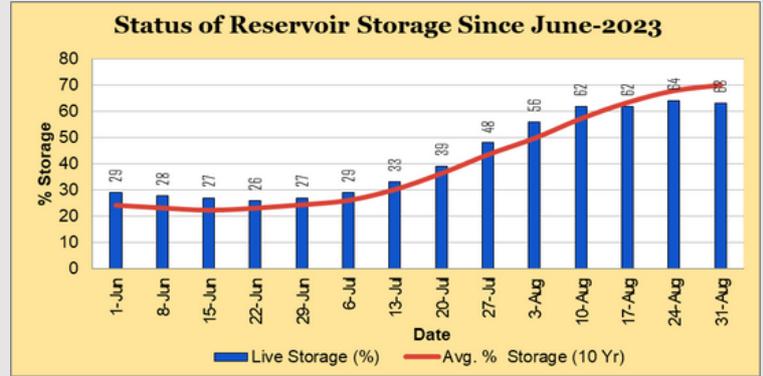
जलाशय निगरानी

के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में अगस्त 2023 के महीने में नीचे नामित चार और जलाशय जोड़े गए हैं।

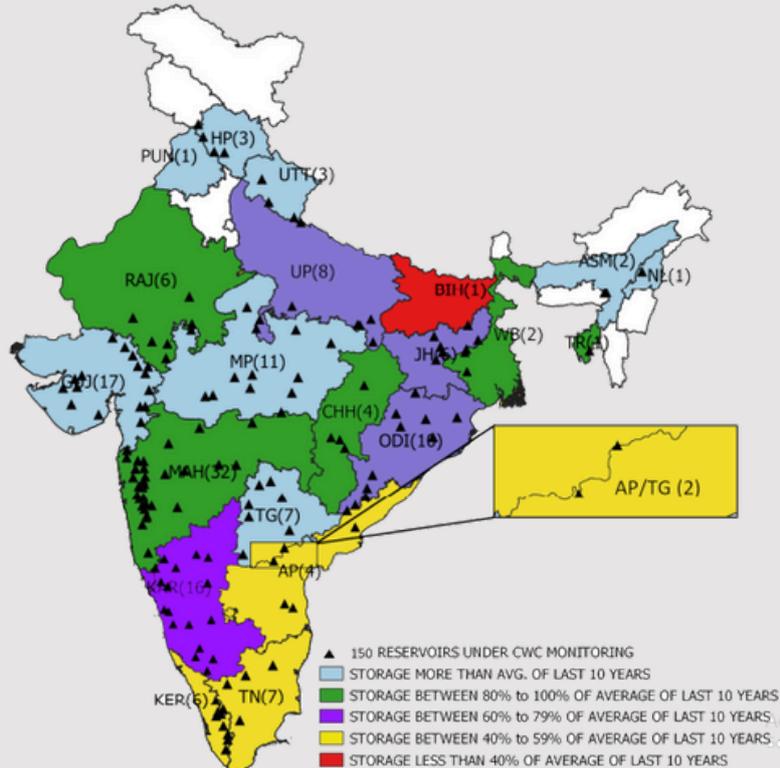
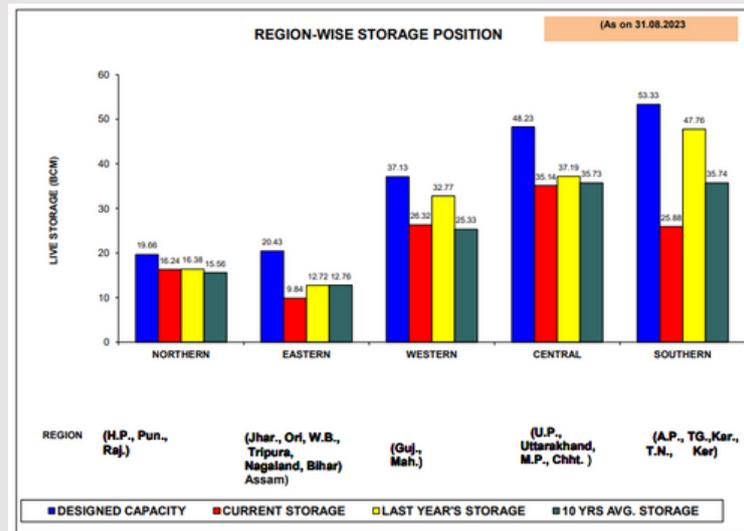
जलाशय का नाम	राज्य	सजीव भंडारण क्षमता
उमरौंग	असम	0.159 बीसीएम
खांडोंग	असम	0.180 बीसीएम
मुसी परियोजना	तेलंगाना	0.123 बीसीएम
कददाम(केएनआर)	तेलंगाना	0.137 बीसीएम
कुल=		0.599 बीसीएम

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 31.08.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 113.417 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 63% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि



के दौरान इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 146.828 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 125.117 बीसीएम था। इस प्रकार, 31.08.2023 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 77% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 91% है।



आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बांध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम



तीस्ता-IV, सिक्किम, आयोजन टी एंड बीडीबीओ, के.ज.आ., कोलकाता, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा एनएचपीसी के सहयोग से किया गया।



बिचोम बांध, कामेंग एचपीएस, अरुणाचल प्रदेश, नीपको लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से बीबीओ, के.ज.आ. गुवाहाटी, एनडीएसए द्वारा आयोजित।



श्रीशीलम बांध, आंध्र प्रदेश जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश के सहयोग से केजीबीओ, के.ज.आ., हैदराबाद, एनडीएसए, दक्षिणी क्षेत्र द्वारा आयोजित



हिराकुंड बांध, ओडिशा, जल संसाधन विभाग, ओडिशा के सहयोग से एम एंड ईआरओ, के.ज.आ., भुवनेश्वर, एनडीएसए द्वारा आयोजित किया गया।



जल संसाधन विभाग, गोवा के सहयोग से एमएसओ, के.ज.आ., बेंगलूर, एनडीएसए द्वारा आयोजित सलौलीम बांध, गोवा



रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश एलजीबीओ, पटना, एनडीएसए द्वारा यूपीजेवीएन, उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित किया गया।

स्वतंत्रता दिवस



केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय नई दिल्ली



केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय नई दिल्ली



के .जी.बी.ओ., हैद्राबाद



एम.टी.बी.ओ., गांधीनगर



राज आ, पुणे



यू जी बी ओ, लखनऊ



श्री राकेश कश्यप, मुख्य अभियंता, आईबीओ, के.ज.आ., चंडीगढ़ ने एसई (सी), आईबीओ और के.ज.आ., जम्मू की टीम के साथ 26.8.2023 को ट्रांस सरु लिक परियोजना के सर्वेक्षण और जांच स्थल का दौरा किया।



सदस्य (आरएम), केन्द्रीय जल आयोग ने 13.08.2023 को यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली के तहत करनाल और मावी हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्थल का निरीक्षण किया।

इतिहास- इडिक्की जलविद्युत परियोजना

केरल में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है। नदियाँ, वर्षा और भू-भाग जलविद्युत क्षमता के विशाल भंडार का योगदान करते हैं।

पल्लीवसल, सेंगुलम, पोरिंगलकुथु, नेरियामंगलम, पन्नियार, सबनगिरी और शोलायार जलविद्युत परियोजनाओं के सफल समापन के बाद, राज्य बिजली बोर्ड ने विशाल इडिक्की जलविद्युत परियोजना शुरू की है, जिसकी स्थापित क्षमता 780 मेगावाट होगी।

पेरियार घाटी में इडिक्की परियोजना राज्य के साथ-साथ भारत के दक्षिणी क्षेत्र की एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना होगी। शक्ति के स्रोत के रूप में इडिक्की की संभावनाओं की जानकारी 1932 में ही मिल गई थी। लेकिन केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग (अब केंद्रीय जल आयोग) इस योजना की जांच 1957 में ही कर सका। यह परियोजना, पश्चिमी घाट की ऊंची श्रृंखलाओं में स्थित है, जिसे केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केंद्रीय जल और विद्युत आयोग और कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से बनाया है। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए पेरियार और चेरुथोनी नदियों के प्रवाह को विनियमित करना है।

परियोजना की विशेषताएं

इडिक्की में तीन ऊंचे बांधों के निर्माण से 2107 मिलियन घन मीटर की सकल क्षमता वाले एक जलाशय की परिकल्पना की गई है, एक इडिक्की घाटी में पेरियार के पार, दूसरा चेरुथोनी के पार व तीसरा कुलमावु में किलिवलीथोडु के पार और (बी) लगभग 30 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 780 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक बिजली सुरंग और दो भूमिगत दबाव शाफ्ट और एक भूमिगत बिजली घर से युक्त जल कंडक्टर प्रणाली के माध्यम से रुके हुए पानी के डायवर्जन की परिकल्पना की गई है।

यह केरल में राज्य के सबसे बड़े जल निकासी बेसिन में स्थित सबसे बड़ी परियोजना थी। इडिक्की में चाप बांध अपनी तरह का पहला और भारत

का दूसरा सबसे ऊंचा बांध था। यह भारत में सबसे बड़ा भूमिगत बिजलीघर का आरंभ करता है, हालांकि यह अपनी तरह का केवल दूसरा है। फिर, चेरुथोनी पर बना बांध केरल में अपनी तरह का सबसे बड़ा और भारत में तीसरा सबसे ऊंचा बांध था।

तीन बांध

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इडिक्की जलाशय तीन ऊंचे बांधों, 100 मीटर कुलमावु चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध, 135.63 मीटर चेरुथोनी कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध, और 170.68 मीटर ऊंचा इडिक्की कंक्रीट चाप बांध द्वारा बनाया गया है। इनमें से, इडिक्की आर्क बांध का विशेष उल्लेख आवश्यक है।

इडिक्की चाप बांध

इडिक्की स्थल पेरियार नदी की एक आदर्श संकीर्ण घाटी में स्थित है, जिसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। यह घाटी नीचे 9.14 मीटर से ऊपर 320.04 मीटर तक खुलती है। बिना किसी दृश्य दोष के उत्कृष्ट चार्नोकाइट चट्टान इस स्थल को उच्च आर्क बांध के लिए उपयुक्त बनाती है।

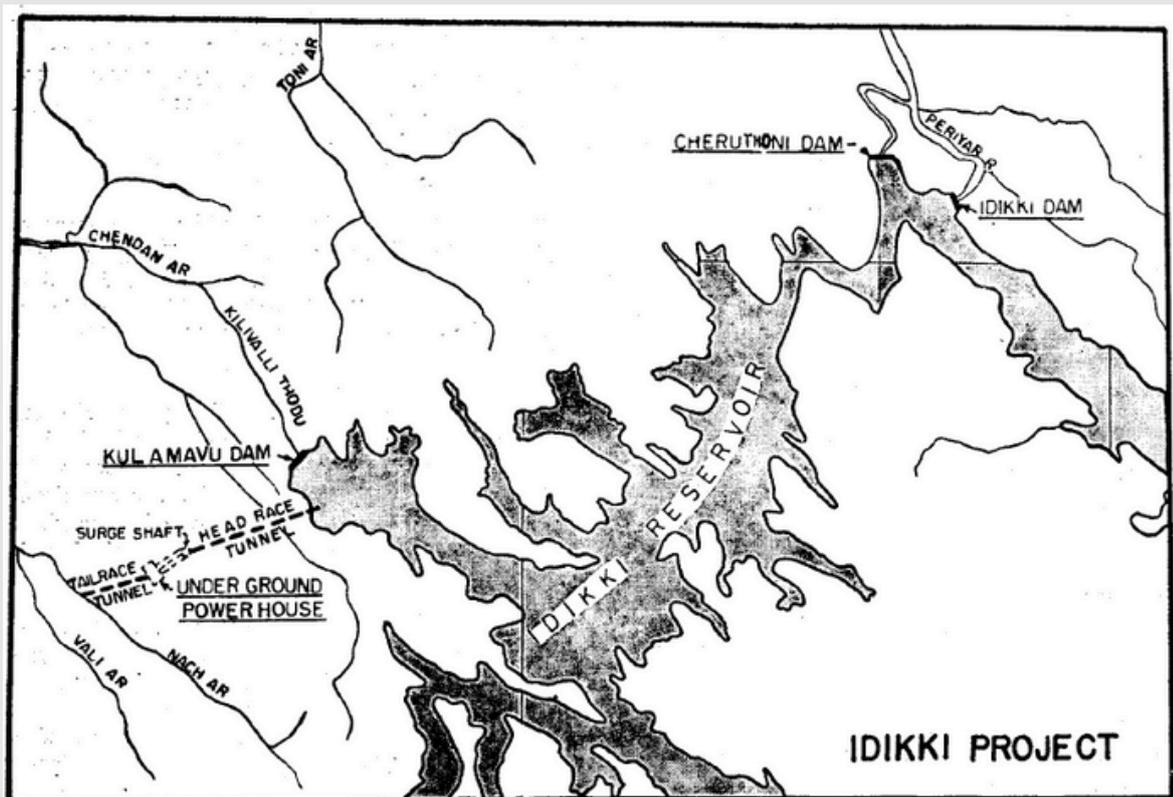
इडिक्की बांध का आकार अनोखा है। बांध के क्षैतिज खंड सममित पाये और अलग-अलग मोटाई के साथ परवल्यिक आकार के हैं। ऊर्ध्वाधर खंड प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों सतहों पर इस आकार के हैं कि परिणामी झिल्ली दोहरे वक्र आकार की होती हैं। बांध प्रोफाइल को ट्रायल लोड विश्लेषण द्वारा डिजाइन किया गया है।

इडिक्की चाप बांध के लिए अंतिम अनुमोदित प्रोफाइल की शीर्ष चौड़ाई 7.62 मीटर और आधार चौड़ाई 19.81 मीटर थी। इस बांध को दुनिया के पहले दस उच्च चाप बांधों में स्थान दिया गया था। यह दुनिया के सबसे पतले चाप बांधों में से एक था।

इडिक्की आर्क बांध का निर्माण 30 अप्रैल 1969 को शुरू हुआ। इसने 4 अक्टूबर 1975 को बिजली उत्पादन शुरू कर दिया।

चेरुथोनी बांध

चेरुथोनी पर बना बांध कंक्रीट से बना सीधा गुरुत्वाकर्षण प्रकार का है,



जो सबसे गहरी नींव से 135.63 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक है। यह शीर्ष पर 650.75 मीटर तक चलता है, जिसकी चौड़ाई 9.14 मीटर है। सबसे गहरी नींव पर, चौड़ाई 108.2 मीटर है। लगभग 1.7 मिलियन घन मीटर की मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता है। इडिक्की जलाशय के लिए स्पिलवे इस बांध में स्थित है, जिसमें प्रत्येक 12.19 मीटर x 9.14 मीटर के पांच वेंट हैं, जो 12.19 मीटर x 9.75 मीटर के पांच रेडियल क्रेस्ट द्वारों द्वारा नियंत्रित हैं। इस बांध में दो बड़े बहिर्गम से 849.5 घन मीटर प्रति सेकंड पानी निकलता है।

कार्य प्रगति

चेरुथोनी बांध के लिए कंक्रीट की पहली बाल्टी 8 मार्च 1969 को डाली गई थी। यह 1976 में पूरा हुआ। इडिक्की और चेरुथोनी दोनों बांधों के कंक्रीट के लिए उच्च स्तर का गुणवत्ता नियंत्रण प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए, इडिक्की में अंतरराष्ट्रीय मानकों की एक सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

कुलमावु बांध

तीसरा बांध, कुलमावु में, पत्थर की चिनाई वाला और भाराश्रित प्रकार का है, जो सबसे गहरी नींव से 100 मीटर ऊंचा है। बांध फरवरी 1977 में खोला गया।

जलाशय

तीन बांधों द्वारा निर्मित जलाशय का पूर्ण जलाशय स्तर (F.R.L.) समुद्र तल से 732.43 मीटर ऊपर है। पानी 59.83 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जलाशय की सकल भंडारण क्षमता 2107 मिलियन घन मीटर है, जबकि लाइव भंडारण 1544.47 मिलियन घन मीटर है।

बिजली संयंत्र

इडिक्की में भूमिगत बिजली घर चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक गुफा, 141.12 मीटर x 19.81 मीटर x 35.05 मीटर, इसके पास 599.23 मीटर लंबी डी-आकार की सुरंग है। स्विचयार्ड जमीन के ऊपर स्थित है, और केबल पावर स्टेशन से स्विचयार्ड तक दो केबल सुरंगों के माध्यम से चलती हैं जो वेंटिलेशन सुरंगों के रूप में भी कार्य करती हैं। 130 मेगावाट की छह उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गईं और पेल्टन प्रकार के छह हाइड्रोलिक टर्बाइनों द्वारा संचालित की गईं। इनमें से तीन इकाइयाँ कनाडा से आयात की गईं और अन्य तीन का निर्माण भारत में किया गया।

पावर स्टेशन से टेलवॉटर को एक सुरंग और एक खुले चैनल के माध्यम से मुवत्तुपुझा नदी की सहायक नदी नाचर में छोड़ा गया।

लागत और लाभ

परियोजना के पहले चरण की अनुमानित लागत 68.21 करोड़ रुपये है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 12 फरवरी 1976 को केरल में कनाडाई सहायता प्राप्त 110 करोड़ रुपये की इडिक्की जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह परियोजना, राज्य में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें सामान्य जल भंडारण, इडिक्की जलाशय बनाने के लिए पेरियार घाटी में तीन बांध शामिल हैं।

इडिक्की गॉर्ज पर पेरियार पर बना चापबांध(आर्चबांध) अपनी तरह का पहला और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा चेरुथोनी के पार है, जो राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कंक्रीट भाराश्रित(ग्रेविटी)बांध है, और तीसरा कुलमावु में किलिवलीथोडु के पार है।

यह विद्युत स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा भूमिगत विद्युत स्टेशन है जो राज्य ग्रिड में 780 मेगावाट बिजली जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने पर 60703 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी और पेरियार नदी के भारी बाढ़ प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा।

इस परियोजना से दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को प्रचुर मात्रा में बिजली का लाभ मिलता है जिसका उपयोग औद्योगिक विकास के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुवत्तुपुझा नदी में वेम्बनाड झील और मुवत्तुपुझा के बीच नेविगेशन की भी अनुमति है, क्योंकि पावर स्टेशन से प्रति सेकंड 41 घन मीटर पानी का नियमित निर्वहन होता है।

इडिक्की जलाशय में लगभग 170 मिलियन घन मीटर की बाढ़ अवशोषण क्षमता का प्रावधान है, जो पेरियार के किनारे के निचले इलाकों में फसलों और जीवन को काफी हद तक सुरक्षित रखता है। कोचीन बंदरगाह क्षेत्र में गाद जमा होने में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा, जलाशय वहां मछली पालन के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है।

विदेशी सहायता

1964 के दौरान, कनाडा सरकार ने स्थायी संयंत्र उपकरण की खरीद के लिए 19.8 मिलियन डॉलर (कनाडाई) के दीर्घकालिक ऋण, निर्माण उपकरण की खरीद और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान के रूप में 7.8 मिलियन डॉलर (कनाडाई) के साथ परियोजना को वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की।

इडिक्की जलविद्युत परियोजना			
विशेषताओं की एक झलक			
स्थान: केरल के कोट्टयम जिले में पेरियार, चेरुथोनी और किलिवलीथोडु पर बांध			
बांध:	इडिक्की	चेरुथोनी	कुलमावु
प्रकार:	कंक्रीट चाप बांध	कंक्रीट सीधा भाराश्रित	चिनाई सीधा भाराश्रित
लंबाई:	365.76मी.	650.24मी.	384.96मी.
अधिकतम ऊंचाई:	170.68मी.	135.63मी.	100मी.
जलाशय:			
सकल भंडारण क्षमता:	2107 मिलियन घन मीटर (74400 मिलियन घन फीट)		
सजीव भंडारण क्षमता:	1544.47 मिलियन घन मीटर (54543 मिलियन घन फीट)		
लाभ:	चरण-I 130 मेगावाट की तीन इकाइयाँ	चरण-II 130 मेगावाट की तीन इकाइयाँ	

(स्रोत: भागीरथ जनवरी 1968)



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री सुनील कुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in